



Lakshya IAS

academy

19

Sep 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS



Mr. R.P. Singh Sir
(MD)



1. सरकार ने अनुसूची एच, एच१ और एक्स दवाओं की निगरानी कड़ी करने के लिए औषधि नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा

मसौदा राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. ७९१ (ई) के तहत, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम,



१९४५ में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अनुसूची एच, एच१ और एक्स दवाएं बेचने वाली चिकित्सा दुकानों में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने का प्रावधान है। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुशंसित यह उपाय अनधिकृत, बिना चिकित्सकीय पर्चे के बिक्री पर अंकुश लगाने, आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से है। खुदरा विक्रेताओं को जांच के लिए तीन महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी और संरक्षित करनी होगी।

मुख्य बिंदु:

- अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी प्रस्तावित: चिकित्सा दुकानों में चिकित्सकीय पर्चे वाली दवाओं की बिक्री पर निगरानी रखने और अनधिकृत पहुंच के विरुद्ध जवाबदेही मजबूत करने के लिए सीसीटीवी निगरानी आवश्यक हो सकती है।
- खुदरा बिक्री विशेष रूप से शामिल: प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य अनुसूची एच, एच१ और एक्स दवाओं का प्रबंधन करने वाली खुदरा चिकित्सा दुकानों को शामिल करना है, जबकि थोक विक्रेता इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
- तीन महीने तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना: औषधालयों को तीन महीने तक निगरानी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की आवश्यकता होगी, जिससे नियामकीय जांच के लिए एक अतिरिक्त पता लगाने योग्य रिकॉर्ड तैयार होगा।

Government Proposes Drug Rule Changes to Tighten Oversight of Schedule H, H1 and X Medicines

Under Draft Gazette Notification G.S.R. 791 (E), the Union Ministry of Health and Family Welfare has proposed amending the Drugs



Rules, 1945 to mandate CCTV surveillance at medical stores selling Schedule H, H1, and X medicines. Recommended by the Drugs Technical Advisory Board, this measure aims to curb unauthorized, prescription-free sales, enhance supply chain transparency, and improve public safety. Retailers must maintain and preserve video recordings for three months for audit checks.

Key Points:

- Mandatory CCTV monitoring proposed: Medical stores may need CCTV surveillance to monitor prescription-drug sales and strengthen accountability against unauthorised access.
- Retail sales specifically covered: The proposed amendment targets retail medical stores handling Schedule H, H1 and X medicines, while wholesalers remain outside its scope.
- Three-month footage retention: Pharmacies would be required to preserve surveillance recordings for three months, creating an additional traceable record for regulatory checks.

2. राजमार्गयात्रा अनुप्रयोग के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वनटैग फास्टैग पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू की

वैश्विक फिनटेक उत्सव २०२६ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 'वनटैग' भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक संयुक्त पोर्टेबिलिटी पहल है। राजमार्गयात्रा मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से उपलब्ध यह सुविधा वाहन मालिकों को मौजूदा भौतिक आरएफआईडी टैग या टैग पहचान संख्या बदले बिना जारीकर्ता बैंकों को बदलने में सक्षम बनाती है। यह सुव्यवस्थित बदलाव परिचालन खर्च को कम करता है, टैग उत्पादन को न्यूनतम करता है और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली के अंतर्गत ग्राहकों की सुविधा बढ़ाता है।

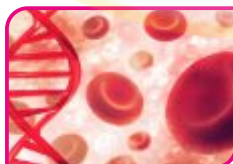


मुख्य बिंदु:

- बिना प्रतिस्थापन के बैंक बदलना: वनटैग फास्टैग उपयोगकर्ताओं को वाहनों पर लगे मौजूदा भौतिक फास्टैग को बनाए रखते हुए अपना जारीकर्ता बैंक बदलने की अनुमति देता है।
- राजमार्गयात्रा पोर्टेबिलिटी सक्षम करता है: उपयोगकर्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के राजमार्गयात्रा अनुप्रयोग के माध्यम से पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे नया भौतिक टैग प्राप्त किए बिना बैंक बदलना आसान हो जाता है।
- बेहतर उपयोगकर्ता लचीलापन: यह सुविधा नियमित जारीकर्ता परिवर्तन के दौरान बैंक संबंधों को भौतिक फास्टैग प्रतिस्थापन से अलग करके उपभोक्ताओं की पसंद बढ़ाती है।

3. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टेम सेल चिकित्सा के उपयोग को विनियमित करने के लिए नई सलाह जारी की

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टेम सेल चिकित्सा पर नियमों को सख्ती से लागू करने वाली सलाह जारी की। मानक नैदानिक अभ्यास केवल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संकेतों के लिए ही अनुमत है, जिसमें मुख्य रूप से रक्त संबंधी घातक रोग और रक्त निर्माण करने वाली स्टेम सेल प्रत्यारोपण का उपयोग करके विशिष्ट रक्त विकार शामिल हैं। आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार जैसी स्थितियों के उपचार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों के तहत अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों तक ही सीमित रखा गया है। अनधिकृत व्यावसायिक प्रशासन या प्रचार पर पंजीकरण रद्द करने और व्यावसायिक कदाचार के दंड का सामना करना पड़ सकता है।



NHAI Introduces OneTag FASTag Portability Feature Through Rajmargyatra App

Launched at Global Fintech Fest 2026 by the Ministry of Road Transport and Highways, 'OneTag' is a joint portability initiative by Indian Highways Management Company Limited and National Payments Corporation of India. Accessible through the Rajmargyatra mobile application, it enables vehicle owners to switch issuer banks without replacing their existing physical RFID tag or tag identification number. This streamlined transition cuts operational expenses, minimizes tag production, and boosts customer convenience within the National Electronic Toll Collection ecosystem.

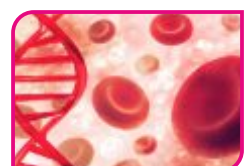


Key Points:

- Bank switching without replacement: OneTag allows FASTag users to change their issuing bank while retaining the existing physical FASTag attached to vehicles.
- Rajmargyatra enables portability: Users can access the portability facility through the NHAI Rajmargyatra application, simplifying bank changes without obtaining another physical tag.
- Improved user flexibility: The facility increases consumer choice by separating bank relationships from physical FASTag replacement during routine issuer changes.

3. Health Ministry Issues New Advisory to Regulate the Use of Stem Cell Therapy

Following a Supreme Court judgment, the Union Health Ministry issued an advisory strictly enforcing regulations on stem cell therapy. Standard clinical practice is permitted solely for Ministry-approved indications, primarily hematological malignancies and specific blood disorders using hematopoietic stem cell transplantation. Treatments for conditions like Autism Spectrum Disorder remain restricted to approved clinical trials under Indian Council of Medical Research guidelines. Unapproved commercial administration or promotion faces cancellation of registration and professional misconduct penalties.



मुख्य बिंदु:

- केवल अनुमोदित उपयोग: स्टेम सेल चिकित्सा केवल उन रोग स्थितियों और संकेतों के लिए नियमित मानक उपचार के रूप में प्रदान की जा सकती है, जिन्हें मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- आत्मकेंद्रित उपचार प्रतिबंधित: आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार के लिए चिकित्सीय स्टेम सेल उपयोग स्थापित अनुसंधान दिशानिर्देशों का पालन करने वाले विधिवत अनुमोदित नैदानिक परीक्षणों तक ही सीमित रहता है।
- उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है: अनधिकृत प्रशासन, प्रचार या चिकित्सकीय पर्चे जारी करने पर व्यावसायिक कदाचार की कार्यवाही और लागू नियमों के तहत दंड हो सकता है।

4. भारत ने खनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा दिया

- खनिज निष्कर्षण को आधुनिक बनाने और पर्यावरणीय अनुपालन लागू करने के लिए, खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से सतत खनन के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली स्थापित की। खनिज संरक्षण और विकास नियमों के तहत लागू यह रूपरेखा स्व-मूल्यांकन प्रारूपों का उपयोग करके खदान पट्टों का मूल्यांकन करती है, जिन्हें आधिकारिक निरीक्षणों द्वारा सत्यापित किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन, संसाधन अनुकूलन, सामाजिक प्रभाव और प्रगतिशील समापन का मूल्यांकन करते हुए, यह एक से पांच सितारा रेटिंग प्रदान करती है, जो पूरे क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार, जिम्मेदार प्रथाओं और संसाधन सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

मुख्य बिंदु:

- उन्नत अन्वेषण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा: भारत के विकसित होते खनन क्षेत्र में खनिज अन्वेषण, परिचालन दक्षता और क्षमताओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान: नवाचार प्रयास तेजी से महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधन सुरक्षा तथा भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक उन्नत प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित हो रहे हैं।
- उद्योग अनुसंधान संबंध मजबूत: खनन कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के बीच सहयोग उन्नत प्रयोगशालाओं, विश्लेषण और उद्योग उन्मुख नवाचार क्षमताओं का समर्थन करता है।

Key Points:

- Approved uses only: Stem cell therapy can be provided as routine standard care only for disease conditions and indications approved by the Ministry.
- Autism treatment restricted: Therapeutic stem cell use for Autism Spectrum Disorder remains restricted to duly approved clinical trials following established research guidelines.
- Violations may attract action: Unauthorised administration, promotion or prescription can lead to professional misconduct proceedings and penalties under applicable regulations.

4. India Pushes Technology-Led Innovation to Strengthen Competitiveness in the Mining Sector

- To modernize mineral extraction and enforce environmental compliance, the Ministry of Mines, through the Indian Bureau of Mines, instituted the Star Rating System for Sustainable Mining. Implemented under the Mineral Conservation and Development Rules, this framework evaluates mine leases using self-assessment templates validated by official inspections. Evaluating environmental management, resource optimization, social impact, and progressive closure, it awards one to five-star ratings, driving technology-led innovation, responsible practices, and resource security across the sector.

Key Points:

- Advanced exploration technologies promoted: Technology-led approaches are being encouraged to improve mineral exploration, operational efficiency and capabilities across India's evolving mining sector.
- Critical minerals receive attention: Innovation efforts increasingly focus on critical minerals and advanced technologies needed for resource security and future industrial requirements.
- Industry research linkages strengthened: Collaboration among mining companies, research institutions and technology providers supports advanced laboratories, analytics and industry-oriented innovation capabilities.

5. श्रम मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया

मुंबई में भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि श्रम शक्ति राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। उन्होंने



रेखांकित किया कि सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल कल्याण राष्ट्रीय विकास के लिए मौलिक बने हुए हैं। ७ करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा के लिए, उन्होंने कल्याण निधियों के इष्टतम उपयोग, श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य डिजिटल श्रम चौक तथा ऑनलाइन उपकर संग्रह पोर्टल जैसी डिजिटल पहलों के कार्यान्वयन का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु:

- सामूहिक प्रयासों पर जोर: सरकार ने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने और सतत विकास उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए हितधारकों के समन्वित प्रयास को आवश्यक बताया।
- श्रमिक कल्याण केंद्र में बना हुआ: श्रम संबंधी पहल भारत भर में सामाजिक संरक्षण, रोजगार के अवसरों, कौशल विकास और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- सतत भविष्य को प्राथमिकता: यह दृष्टिकोण श्रम नीतियों को व्यापक विकास लक्ष्यों से जोड़ता है, समावेशी भागीदारी और मजबूत सामाजिक संरक्षण तंत्र को प्रोत्साहित करता है।

6. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एससीडीपीएम ५.० के तहत स्वच्छता और प्रशासनिक दक्षता को आगे बढ़ाया

लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान के तहत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसके संस्थानों ने प्रशासनिक दक्षता में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं।



१० कार्यालयों में २० स्वच्छता अभियान चलाकर, मंत्रालय ने उत्पादक उपयोग के लिए ५४,८१५ वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त किया और कबाड़ निपटान से १.५७ करोड़ रुपये उत्पन्न किए। व्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन के परिणामस्वरूप ७५० भौतिक फाइलों और १७७ ई-फाइलों को बंद किया गया, साथ ही सार्वजनिक शिकायतों और मंत्रिमंडल प्रस्तावों के लिए १०० प्रतिशत समाधान दर हासिल की गई।

Labour Ministry Calls for Collective Action to Promote Social Justice and Sustainable Development

Addressing the National Conference on Building and Other Construction Workers in Mumbai, Union Labour Minister Dr. Mansukh Mandaviya stated that labor power is integral to nation-building. He highlighted that social security and workforce welfare remain fundamental to national development. To protect over seven crore construction workers, he urged optimum utilization of welfare funds, effective execution of labor codes, and implementation of digital initiatives like the State Digital Labour Chowk and Online Cess Collection Portals.



Key Points:

- Collective efforts emphasised: The government highlighted coordinated action among stakeholders as essential for advancing social justice and supporting sustainable development objectives.
- Worker welfare remains central: Labour-related initiatives continue focusing on social protection, employment opportunities, skills development and dignified working conditions across India.
- Sustainable future prioritised: The approach connects labour policies with broader development goals, encouraging inclusive participation and stronger social protection mechanisms.

6. Ministry of Earth Sciences Advances Cleanliness and Administrative Efficiency Under SCDPM 5.0

Under the Special Campaign for Disposal of Pending Matters, the Ministry of Earth Sciences and its institutes achieved major administrative efficiency milestones. Conducting 20 cleanliness drives across ten offices, the ministry freed 54,815 square feet of office space for productive use and generated 1.57 crore rupees from scrap disposal. Systematic record management led to closing 750 physical files and 177 e-files, alongside achieving a 100 percent addressal rate for public grievances and cabinet proposals.



मुख्य बिंदु:

- स्वच्छता अभियान का विस्तार: दिसंबर २०२५ और अगस्त २०२६ के बीच १० कार्यालयों और संस्थानों में २० स्वच्छता अभियान चलाए गए।
- कार्यालय स्थान का अनुकूलन: व्यवस्थित निपटान और संगठनात्मक सुधारों के माध्यम से अभियान ने उत्पादक उपयोग के लिए ५४,८१५ वर्ग फुट कार्यालय स्थान मुक्त किया।
- अभिलेख प्रबंधन में सुधार: व्यवस्थित फाइल छंट्टाई और निपटान गतिविधियों ने प्रशासनिक दक्षता का समर्थन किया, साथ ही सुव्यवस्थित दस्तावेजीकरण और डिजिटल अभिलेखों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया।

7. भारत ने जी२० ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला

- ✎ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में, भारत ने ह्यूस्टन में संयुक्त राज्य अमेरिका की जी२० अध्यक्षता के तहत आयोजित जी२० ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, सस्ती और विश्वसनीय आधारभूत ऊर्जा पर जोर दिया, जिसमें इसकी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता ५५२ गीगावाट तक पहुंच गई है और गैर-जीवाश्म स्रोत आधे से अधिक हो गए हैं। भारत ने पुनर्चक्रण और मूल्यवर्धन के माध्यम से सुव्यवस्थित नियामक दक्षता, डिजिटल अनुमति उपकरण और लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की वकालत की।



मुख्य बिंदु:

- सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति पर जोर: भारत ने सुरक्षित, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा को विकास के लिए आवश्यक बताया, विशेष रूप से बढ़ती मांग का सामना कर रही विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में।
- तीन स्तंभों ने चर्चाओं का मार्गदर्शन किया: बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती आधारभूत ऊर्जा, नियामक दक्षता तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा हुई।
- महत्वपूर्ण खनिज सहयोग आगे बढ़ा: चर्चाओं में आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और खनिज मूल्यवर्धन को मजबूत करने के लिए नवाचार, चक्रीयता, निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया गया।

Key Points:

- Cleanliness drives expanded: Twenty cleanliness drives were conducted across ten offices and institutes between December 2025 and August 2026.
- Office space optimised: The campaign freed 54,815 square feet of office space for productive use through systematic disposal and organisational improvements.
- Records management improved: Systematic file weeding and disposal activities supported administrative efficiency while encouraging streamlined documentation and greater use of digital records.

7. India Highlights Energy Security Priorities at G20 Energy Abundance Ministerial Meeting

- ✎ Led by Union Minister Manohar Lal in Houston, India participated in the G20 Energy Abundance Ministerial Meeting held under the United States G20 Presidency. India emphasized secure, affordable, and reliable baseload energy for economic growth, highlighting its installed power generation capacity reaching 552 gigawatts with non-fossil sources exceeding half. India advocated for streamlined regulatory efficiency, digital permitting tools, and resilient critical mineral supply chains through recycling and value addition.



Key Points:

- Secure energy supply stressed: India emphasised secure, affordable and reliable energy as essential for development, particularly across developing economies facing growing demand.
- Three pillars guided discussions: The meeting addressed energy security and affordable baseload, regulatory efficiency, and critical minerals with resilient supply chains.
- Critical minerals cooperation advanced: Discussions encouraged innovation, circularity, investment and international cooperation to diversify supply chains and strengthen mineral value addition.

8. डॉ. जितेंद्र सिंह ने अधिक प्रतिस्पर्धी खनन उद्योग के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दिया

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर दिया कि महत्वपूर्ण खनिज और उन्नत सामग्री भारत की ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।



संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण की वकालत करते हुए, उन्होंने घरेलू संसाधनों को वैश्विक साझेदारियों के साथ जोड़ने, प्रारंभिक उद्योग-अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देने और घरेलू तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रयोगशाला से बाजार तक की दूरी को कम करने के लिए, उन्होंने विज्ञान आधारित स्टार्टअप को स्थापित उद्योगों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिससे आयात निर्भरता कम हो और तकनीकी परिवर्तन के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण हो।

मुख्य बिंदु:

- प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित किया गया: सरकार ने प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार खनन क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और मजबूत अनुसंधान-उद्योग संबंधों को महत्वपूर्ण साधन बताया।
- महत्वपूर्ण खनिज अनुसंधान का विस्तार: नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ मृदा तत्वों और उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर केंद्रित विशेष प्रयोगशालाओं और साझेदारियों का समर्थन कर रहे हैं।
- प्रयोगशाला से बाजार तक संबंध मजबूत: स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में बदलने के लिए विज्ञान संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग के बीच अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

9. समुदाय आधारित विज्ञान पहल राजस्थान में तपेदिक का पता लगाने और प्रबंधन को मजबूत करती है

तपेदिक उन्मूलन में तेजी लाने के लिए, राजस्थान ने संवेदनशील और जनजातीय आबादी के बीच सक्रिय मामलों की खोज के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम पोर्टेबल एक्स-रे उपकरण तैनात किए।



पहचाने गए मामलों में तेजी से पुष्टि के लिए एक्सपर्ट आणविक परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में अंतर, प्रवासन और निदान में देरी जैसी चुनौतियों का समाधान करते हुए, यह समुदाय आधारित दृष्टिकोण प्रारंभिक जांच, उपचार के पालन और अनुवर्ती कार्यवाई को सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों के निर्धारित लक्ष्य से पांच वर्ष पहले देशभर से तपेदिक को समाप्त करना है।

Dr Jitendra Singh Stresses Technology Adoption for Building a More Competitive Mining Industry

Union Minister Dr. Jitendra Singh emphasized that critical minerals and advanced materials are vital for India's energy security, industrial competitiveness, and strategic self-reliance. Advocating a whole-of-nation approach, he called for combining domestic resources with global partnerships, fostering early industry-research linkages, and strengthening domestic technological capabilities. To bridge the lab-to-market gap, he highlighted the need to integrate science startups with established industries, reducing import dependencies and building resilient supply chains for technological transformation.



Key Points:

- Technology adoption encouraged: The government highlighted advanced technologies and stronger research-industry connections as important tools for developing competitive and future-ready mining capabilities.
- Critical mineral research expanded: Innovation ecosystems are supporting specialised laboratories and partnerships focused on critical minerals, rare earths and advanced analytical capabilities.
- Lab-to-market links strengthened: Greater collaboration between science institutions, startups and industry is being encouraged to translate indigenous technologies into commercial applications.

9. Community-Based Science Initiative Strengthens Tuberculosis Detection and Management in Rajasthan

To accelerate tuberculosis elimination, Rajasthan deployed artificial intelligence-enabled portable X-ray devices for active case finding across vulnerable and tribal populations. Identified cases undergo Xpert molecular testing for rapid confirmatory diagnosis. Addressing challenges like healthcare access gaps, migration, and diagnostic delays, this community-based approach delivers early screening, treatment adherence, and follow-up. It aligns with the National TB Elimination Programme to eliminate tuberculosis nationwide five years ahead of the Sustainable Development Goals target.



मुख्य बिंदु:

- समुदाय की भागीदारी मजबूत हुई: राजस्थान में विज्ञान आधारित पहल संवेदनशील समुदायों के बीच तपेदिक उन्मूलन में सहायता के लिए स्थानीय भागीदारी, जागरूकता और क्षमता निर्माण पर जोर देती हैं।
- तपेदिक का पता लगाने को तकनीकी सहायता मिली: राजस्थान में तपेदिक रोगियों की पहचान करने और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की अनुवर्ती कार्रवाई को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण तैनात किए गए हैं।
- जनजातीय चुनौतियों का समाधान: समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण जनजातीय आबादी में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच, प्रवासन, जागरूकता की कमी, भेदभाव और उपचार संबंधी कठिनाइयों जैसी बाधाओं को ध्यान में रखते हैं।

10. प्रौद्योगिकी के माध्यम से शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए नया डिजिटल मंच शुरू किया गया

- ✍ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रो. अजय कुमार सूद ने जीवन चक्र आकलन रूपरेखा और ग्रीनहाउस गैस गणक वेब अनुप्रयोग का शुभारंभ किया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के लिए जीवन चक्र आकलन रूपरेखा के विकास परियोजना के तहत विकसित यह डिजिटल मंच शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रणालियों का मूल्यांकन, योजना और अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है। यह शुद्ध, टाले गए और रसद संबंधी उत्सर्जन पर विस्तृत मापदंड प्रदान करता है, जिससे नगरपालिकाएं अपशिष्ट प्रसंस्करण विकल्पों की तुलना कर सकती हैं और कम उत्सर्जन वाली, जलवायु अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को अपना सकती हैं।



मुख्य बिंदु:

- डिजिटल निगरानी मजबूत हुई: नई प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियां संग्रह, प्रसंस्करण और स्वच्छता संचालन को जोड़ सकती हैं तथा शहरी अपशिष्ट प्रबंधन अधिकारियों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकती हैं।
- साक्ष्य आधारित योजना सक्षम हुई: एकीकृत डैशबोर्ड अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी जानकारी को एकीकृत डिजिटल प्रणालियों में एक साथ लाकर परिचालन निगरानी, योजना और निर्णय लेने में सहायता करते हैं।
- नगरपालिका शासन को समर्थन: डिजिटल उपकरण रिपोर्टिंग, अनुपालन निगरानी और क्षेत्रीय संचालन, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा शहरी प्राधिकरणों के बीच समन्वय में सुधार कर सकते हैं।

Key Points:

- Community participation strengthened: Science-based initiatives in Rajasthan emphasise local participation, awareness and capacity building to support tuberculosis elimination across vulnerable communities.
- TB detection receives technological support: Artificial intelligence tools have been deployed to identify tuberculosis patients and strengthen follow-up of high-risk individuals across Rajasthan.
- Tribal challenges addressed: Community-focused approaches consider barriers including healthcare access, migration, awareness gaps, discrimination and treatment-related difficulties in tribal populations.

10. New Digital Platform Launched to Improve Urban Waste Management Through Technology

- ✍ Principal Scientific Adviser to the Government of India, Prof. Ajay Kumar Sood, launched a Life Cycle Assessment framework and greenhouse gas calculator web application. Developed under the Development of LCA Framework for Solid Waste Management Technologies project, this digital platform enables Urban Local Bodies to evaluate, plan, and optimize solid waste systems. It provides detailed metrics on net, avoided, and logistical emissions, enabling municipalities to compare waste processing options and adopt low-emission, climate-resilient waste management practices.



Key Points:

- Digital monitoring strengthened: New technology-enabled platforms can connect collection, processing and sanitation operations while providing real-time visibility for urban waste management authorities.
- Evidence-based planning enabled: Integrated dashboards support operational monitoring, planning and decision-making by bringing waste-management information together within unified digital systems.
- Municipal governance supported: Digital tools can improve reporting, compliance tracking and coordination between field operations, processing facilities and urban authorities.

दैनिक समसामयिक

DAILY

CURRENT AFFAIRS

MCQs

प्रश्नोत्तरी

Q1. सितंबर २०२६ में शुरू किया गया डिजिटल मंच मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के किस पहलू का आकलन करने में सहायता करता है?

- (a) अपशिष्ट परिवहन लागत
- (b) शहरी जल खपत
- (c) नगरपालिका कर संग्रह
- (d) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन पदचिह्न

Q2. २०२६ में, एक समुदाय आधारित विज्ञान पहल ने राजस्थान में तपेदिक की जांच को काफी बढ़ाया। राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा तपेदिक को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कौन-सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है?

- (a) २०२७-२०२८
- (b) २०२५-२०२६
- (c) २०३०-२०३१
- (d) २०३५-२०३६

Q3. सितंबर २०२६ में डॉ. जितेंद्र सिंह की टिप्पणियों के अनुसार, भारत के खनन और महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए कौन-सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है?

- (a) उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना और स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना
- (b) वैज्ञानिक अनुसंधान को कम करना
- (c) निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित करना
- (d) आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता बढ़ाना

Q4. सितंबर २०२६ में, भारत ने जी२० ऊर्जा प्रचुरता मंत्रिस्तरीय बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह जी२० शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था?

- (a) ब्राजील
- (b) दक्षिण अफ्रीका
- (c) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (d) भारत

Q5. सितंबर २०२६ में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एससीडीपीएम ५.० के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियों की सूचना दी। सरकारी प्रशासनिक सुधारों में संक्षिप्त नाम 'एससीडीपीएम' का पूरा नाम क्या है?

- (a) डिजिटल मुद्रण और प्रबंधन के लिए विशेष अभियान
- (b) केंद्रीकृत विकास और नीति निगरानी प्रणाली
- (c) सार्वजनिक मंत्रालयों के लिए सतत स्वच्छता अभियान
- (d) लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान

Q1. The digital platform launched in September 2026 helps Urban Local Bodies primarily to assess what aspect of solid waste management?

- (a) Waste transportation costs
- (b) Urban water consumption
- (c) Municipal tax collection
- (d) Greenhouse gas emissions and carbon footprint

Q2. In 2026, a community-based science initiative significantly enhanced TB screening in Rajasthan. What is the target year set by the Government of India to completely eliminate Tuberculosis under the National TB Elimination Programme (NTEP)?

- (a) 2027-2028
- (b) 2025-2026
- (c) 2030-2031
- (d) 2035-2036

Q3. According to Dr. Jitendra Singh's September 2026 remarks, which approach is important for improving India's mining and critical minerals ecosystem?

- (a) Adopting advanced technologies and strengthening indigenous capabilities
- (b) Reducing scientific research
- (c) Restricting private-sector participation
- (d) Increasing dependence on imported technologies

Q4. In September 2026, India actively participated in the G20 Energy Abundance Ministerial Meeting. Under which country's presidency was this G20 summit held?

- (a) Brazil
- (b) South Africa
- (c) United States
- (d) India

Q5. September 2026, the Ministry of Earth Sciences (MoES) reported significant achievements under SCDPM 5.0. What does the acronym 'SCDPM' stand for in government administrative reforms?

- (a) Special Campaign for Digital Printing and Management
- (b) System for Centralized Development and Policy Monitoring
- (c) Sustainable Cleanliness Drive for Public Ministries
- (d) Special Campaign for Disposal of Pending Matters

Q6. सितंबर २०२६ के भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, डॉ. मनसुख मांडविया ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल का कल्याण किसके लिए मौलिक है?

- (a) औद्योगिक निर्यात
- (b) डिजिटल परिवर्तन
- (c) राष्ट्रीय विकास
- (d) कृषि विकास

Q7. खनिज निष्कर्षण को आधुनिक बनाने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, खान मंत्रालय ने भारत में खदानों के लिए कौन-सी प्रमुख रैंकिंग प्रणाली शुरू की?

- (a) सतत खनन के लिए रेटिंग प्रणाली
- (b) हरित रेटिंग योजना स्टार
- (c) खनन दक्षता सूचकांक (एमईआई)
- (d) शुद्ध-शून्य निष्कर्षण प्रमाणन

Q8. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने २०२६ में स्टेम सेल चिकित्सा के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए। भारत में वर्तमान चिकित्सा नियमों के अनुसार, स्टेम सेल चिकित्सा किस श्रेणी के विकारों के लिए उपचार की मानक पद्धति के रूप में आधिकारिक रूप से अनुमोदित है?

- (a) अल्जाइमर रोग के लिए तंत्रिका संबंधी पुनर्जनन
- (b) वृद्धावस्था रोधी और सौंदर्य वृद्धि प्रक्रियाएं
- (c) रक्त संबंधी घातक रोग और विशिष्ट रक्त विकार
- (d) प्राथमिक मांसपेशीय अपक्षय रोग और रीढ़ की हड्डी की चोट की पुनर्बहाली

Q9. सितंबर २०२६ में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'वनटैग' फास्टैग पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू की। इस सेवा का उपयोग करने के लिए कौन-सा आधिकारिक मोबाइल अनुप्रयोग सक्षम बनाता है?

- (a) एमपरिवहन
- (b) राजमार्गयात्रा
- (c) फास्टैग मित्र
- (d) भारत मार्ग

Q10. सितंबर २०२६ में औषधि नियमों में प्रस्तावित संशोधनों के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा दुकानों के लिए कौन-सा नया नियामक सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किया है?

- (a) बायोमेट्रिक उपस्थिति
- (b) अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी
- (c) ऑनलाइन भुगतान सत्यापन
- (d) दैनिक भौतिक निरीक्षण

Q6. During the September 2026 National Conference on Building and Other Construction Workers, Dr. Mansukh Mandaviya emphasised that social security and welfare of the workforce are fundamental to what?

- (a) Industrial exports
- (b) Digital transformation
- (c) National development
- (d) Agricultural growth

Q7. To modernize mineral extraction and promote sustainable practices, the Ministry of Mines launched which flagship ranking system for mines in India?

- (a) Rating System for Sustainable Mining
- (b) Green Rating Scheme Star
- (c) Mining Efficiency Index (MEI)
- (d) Net-Zero Extraction Certification

Q8. The Union Health Ministry issued strict guidelines in 2026 regarding Stem Cell Therapy. According to current medical regulations in India, for which category of disorders is stem cell therapy officially approved as a standard line of treatment?

- (a) Neurological regeneration for Alzheimer's disease
- (b) Anti-aging and cosmetic enhancement procedures
- (c) Hematological malignancies and specific blood disorders
- (d) Primary muscular dystrophies and spinal injury restoration

Q9. In September 2026, National Highways Authority of India (NHAI) introduced the 'OneTag' FASTag portability feature. Which official mobile application enables users to access this service?

- (a) mParivahan
- (b) Rajmargyatra
- (c) FASTag Mitra
- (d) Bharat Marg

Q10. What new regulatory safeguard has the Union Health Ministry proposed for medical stores under the September 2026 drug-rule amendments?

- (a) Biometric attendance
- (b) Mandatory CCTV surveillance
- (c) Online payment verification
- (d) Daily physical inspection

उत्तरमाला (Answer Key)

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | D | 2 | B | 3 | A | 4 | C | 5 | D | 6 | C | 7 | A | 8 | C | 9 | B | 10 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

